हिंदी दैनिक
न्यूज़ वायरस
वर्ष : 11 अंक : 04 देहरादून, शनिवार, 18 जून, 2022 मूल्य : एक रुपया पृष्ठ : 08

अग्निपथ योजना, युवाओं को भड़का रहा विपक्ष : अजय भट्ट 4

भगत सिंह कोश्यारी राजनीति के पुरोधा, जन नेता कुशल प्रशासक एवं विचारक है : मुख्यमंत्री धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ''द लीजेण्ड ऑफ कोश्यारी भगत दा'' पुस्तक का विमोचन,रवि मोहन अग्रवाल के प्रयास और समर्पण को सराहा

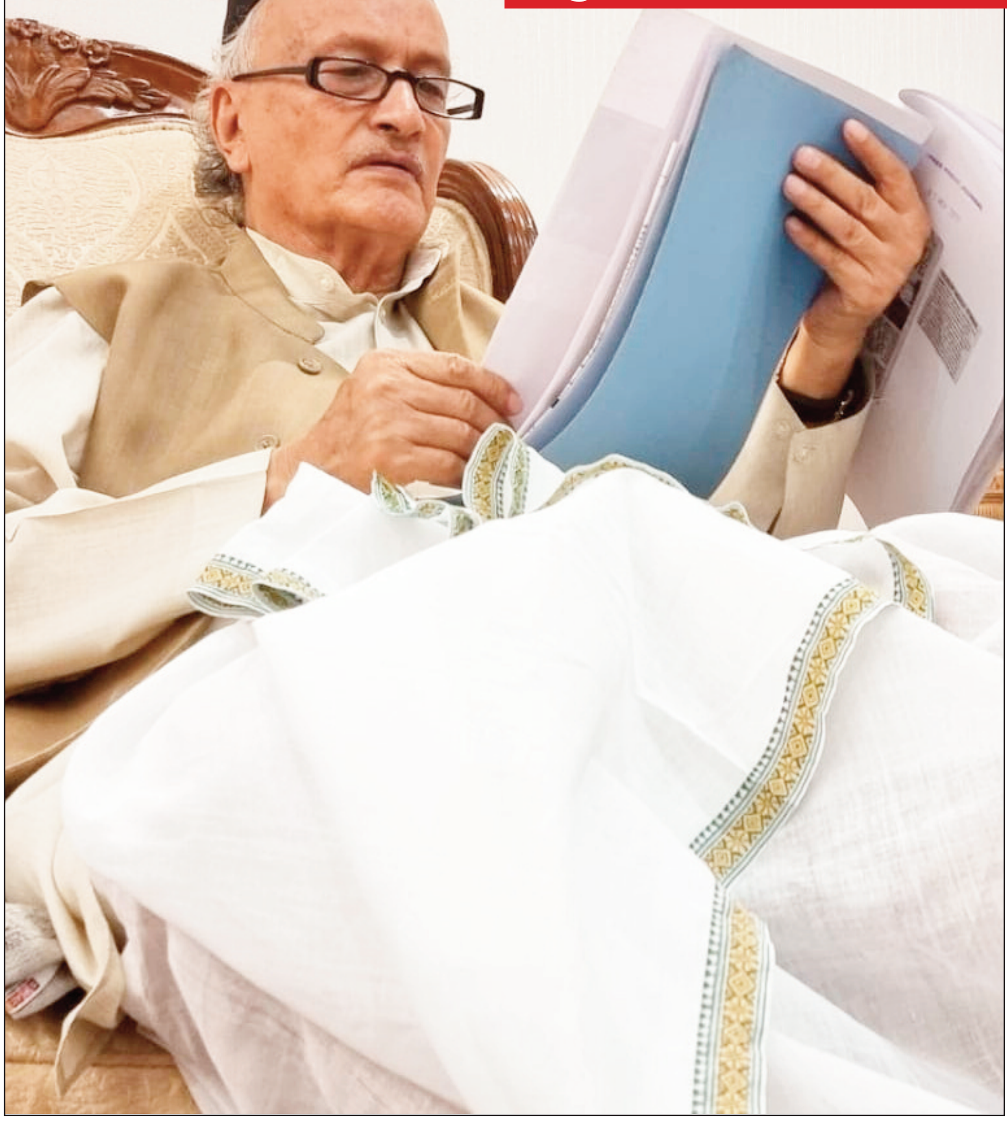

मो.सलीम सैफी,समूह संपादक
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित पुस्तक द लीजेण्ड ऑफ कोश्यारी भगत दा का विमोचन किया। उन्होंने पुस्तक के लेखक एवं प्रकाशकों को भगत सिंह कोश्यारी के जन्म दिन के अवसर पर पुस्तक का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित करने के लिये आभार भी व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने भगत सिंह कोश्यारी को जन्म दिवस की शुभकामनाये देते हुए कहा कि उनके व्यक्तित्व का हर पहलू प्रेरणादायी है। वे सहजता की प्रतिमूर्ति है वे व्यक्ति के साथ मिशन है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी वास्तव में भारतीय राजनीति के पुरोधा, जन नेता, कुशल प्रशासक एवं विचारक है। वे राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं गौरव के भी प्रतीक है। अपने जीवन की शुरूआत में ही उन्होंने एक राजनेता के साथ ही कुशल शिक्षक के रूप में समाज को दिशा देने का कार्य किया। ऐसे विद्धान एवं सरल स्वभाव के व्यक्तित्व का देश के प्रमुख राज्य महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में उपस्थिति हम सबको गौरवान्वित करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें भगत सिंह कोश्यारी के सानिध्य में रहकर सामाजिक व राजनैतिक क्षेत्र में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगत सिंह कोश्यारी ने सामान्य परिवेश में रहकर शिखर छूने का कार्य किया है तथा अपने पुरूषार्थ से महानता प्राप्त की है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में 30 वर्षों से लम्बित टिहरी डैम को उसके पूर्ण स्वरूप में लाने का श्रेय भी कोश्यारी को है। प्रदेश में ऊर्जा मंत्री रहते उन्होंने इसके लिये राजनैतिक नफा नुकसान की चिंता न करते हुए बांध बनाने में अपना योगदान दिया। भगत सिंह कोश्यारी सभी नीतिगत विषयों के जानकार, दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने सीख दी कि पूरे प्रदेश को समझने, जन समस्याओं की जानने का प्रयास करो, वक्त आने पर व्यक्ति के अच्छे कार्यों को

रवि मोहन अग्रवाल

पहचान मिलती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको साथ लेकर चलना, छोटे-बड़े का भेदभाव न कर सभी को आगे बढ़ाने में मदद करने की भी सीख हमें कोश्यारी से मिली है। उनका जीवन हम सबके लिये निश्चित रूप में अनुकरणीय एवं प्रेरणादायी है।

इस अवसर पर राज्य सभा सांसद नरेश बंसल ने पुस्तक को प्रेरणादायी बताते हुए भगत दा को बड़े दिल वाला जन नेता बताया। वे चौपाल में रहें या राजभवन में उनकी दिनचर्या साधारण ही रहती है। उन्होंने कहा कि उन्हें भी भगत सिंह कोश्यारी की छत्र छाया में आगे बढ़ने का मौका मिला है। पुस्तक के लेखक बी0एस0जोगदण्डे तथा संकल्पना सहयोगी रविमोहन अग्रवाल ने पुस्तक के विषय वस्तु की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन देवेन्द्र भसीन द्वारा किया गया।

इस अवसर पर विधायक सविता कपूर, सरिता आर्य, सुरेश गडिया, मोहन सिंह बिष्ट, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार के साथ ही प्रदेश एवं महाराष्ट्र से आये गणमान्य लोग उपस्थित थे।

आदेश किया नज़रंदाज़ तो डीएम डॉ आर राजेश कुमार ने मदिरा शॉप पर ठोंका एक लाख का जुर्माना

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार के आदेश को नज़र अंदाज़ करना वाइन शॉप को भारी पड़ा है। आबकारी विभाग द्वारा सर्वे चौक डालनवाला शराब की दुकान का किया 110000 (एक लाख 10 हजार) का चालान। शराब की दुकान से दो बार 'यहां पर ओवर रेटिंग नहीं होती है' संबंधी बैनर हटाए पाए जाने पर कार्यवाही अमल में लाई गई।जनपद में शराब की बिक्री पर ओवर रेटिंग हेतु छापामारी भी लगातार जारी है। जिलाधिकारी डॉ0 आर राजेश कुमार ने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही शराब की ओवर रेटिंग की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए

जिला आबकारी अधिकारी को जनपद अवस्थित शराब की दुकानों में ' यहाँ पर ओवर रेटिंग नहीं की जाती है,' का बैनर/फ्लैक्स लगाने तथा शराब की ओवर रेटिंग करने व बैनर पोस्टर चस्पा न करने वाली दुकानों पर अर्थदण्ड की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे।

जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार के निर्देशों का गंभीरता से पालन न करने पर आबकारी विभाग द्वारा शराब की दुकानों पर यहां पर ओवर रेटिंग नहीं की जाती है, की पोस्टर बैनर चस्पा करवाए गए, देहरादून सर्वे चैक (डालनवाला) शराब की दुकान पर पोस्टर, बैनर चस्पाए गए थे, जिसे हटाने पर उक्त दुकान का 10 हजार का चालान किया गया था तथा पोस्टर, बैनर चस्पा करने के निर्देश दिए गए। शुक्रवार को निरीक्षण के दौरान इस मदिरा की दुकान में पोस्टर, बैनर दूसरी बार हटाये जाने पर शराब की दुकान का चालान करते हुए 1 लाख का अर्थदण्ड लगाया गया।

जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि शराब की ओवर रेटिंग पर चलाये जा रहे अभियान को हल्के में लेने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा इसकी पुनरावृत्ति करने वालो पर आबकारी एक्ट में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार सख्त कार्यवाही की जाए। साथ ही आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में नियमित छापेमारी अभियान चलाते हुए प्रतिदिन कृत कार्यवाही से अवगत कराए। वहीं जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश के पालन कराने के लिए दुकानों पर छापामारी अभियान

जारी है। जिन दुकानों में फ्लेक्स पोस्टर नहीं पाए जा रहे हैं एवं ओवर रेटिंग तथा अन्य कमियां पाए जाने पर चालान व कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

क्या आप जानते हैं देश की पहली प्राइवेट ट्रेन की खूबियां, भारत गौरव स्कीम

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

भारत के पहले प्राइवेट ट्रेन सर्विस की शुरुआत को हो गई है । 14 जून को कोयंबटूर से भारत गौरव स्कीम के तहत इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन शुरू हो चुकी है। इसका सबसे पहला सफर तमिलनाडु के कोयंबटूर से शिरडी के बीच रहा। भारतीय रेल ने 20 डिब्बों वाली इस ट्रेन को दो साल के लिए प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को लीज पर दिया है। इसके 20 डिब्बों में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड क्लास एसी कोच और स्लीपर कोच शामिल हैं। ट्रेन में एक साथ 1500 लोग सफर कर सकते हैं। हर महीने कम से कम तीन यात्राएं हो सकेंगी।

ट्रेन में हैं 20 कोच

भारत गौरव ट्रेन कोयंबटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के लिए मंगलवार को शाम 6 बजे शुरू हुई और ट्रेन का 16 जून को सुबह 7:25 बजे साईनगर शिरडी पहुंचने का वक्त मुकर्रर किया गया है। ये ट्रेन तिरुपुर, इरोड, सेलम, येलहंका, धर्मावरम, मंत्रालयम रोड और वाडी पर रुकेगी। कोयंबटूर से आगे की यात्रा के दौरान यह भारत गौरव ट्रेन मंत्रालयम मंदिर में दर्शन की सुविधा के लिए मंत्रालयम रोड स्टेशन पर 5 घंटे के लिए रुकेगी। वापसी में ट्रेन साईनगर शिरडी से कोयंबटूर के लिए भारत गौरव ट्रेन 17 जून 2022 शुक्रवार को 07:25 बजे शुरू होगी। ट्रेन 18 जून 2022 शनिवार को 12:00 बजे कोयंबटूर पहुंचेगी। ये फिर धर्मावरम, येलहंका, सेलम, इरोड और तिरुपुर रुकेगी। इस ट्रेन में कुल 20

कोच हैं। पहले एसी कोच -1, 2-टियर एसी कोच – 3, 3-टियर एसी कोच-8, स्लीपर क्लास कोच-5, पेंट्री कार-1 और लगेज-कम-ब्रेक वैन के 2 कोच हैं।

ट्रेन में मिलेंगी ये सुविधाएं

ट्रेन में कोई बीमार हो गया तो उसके लिए एक डॉक्टर होंगेट्रेन में रेलवे पुलिस बल के साथ प्राइवेट सिक्योरिटी भी होगीट्रेन पर इलेक्ट्रीशियन और एसी मैकेनिक, फायर और सेफ्टी के लिए अधिकारी होंगे

भारत गौरव स्कीम के तहत यात्रा

पिछले साल 23 नवंबर 2021 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने थीम-आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेन्स भारत गौरव ट्रेन्स का ऐलान किया था। इसका लक्ष्य भारत के ऐतिहासिक स्थानों और रिच कल्चरल हेरिटेज को रेलमार्ग से जोड़ना है, ताकि देश और दुनिया के लोग आसानी से इन स्थानों पर पहुंच सकें। इस स्कीम के तहत सर्विस प्रोवाइडर यात्रियों को रेल यात्रा, रहना, खाना, साइटसीइंग यानी टूरिस्ट प्लेस में घुमाना इत्यादि का पैकेज ऑफर करेगी।

धामी सरकार की बड़ी उपलब्धि, पहाड़ी राज्यों में पाया शानदार मुकाम

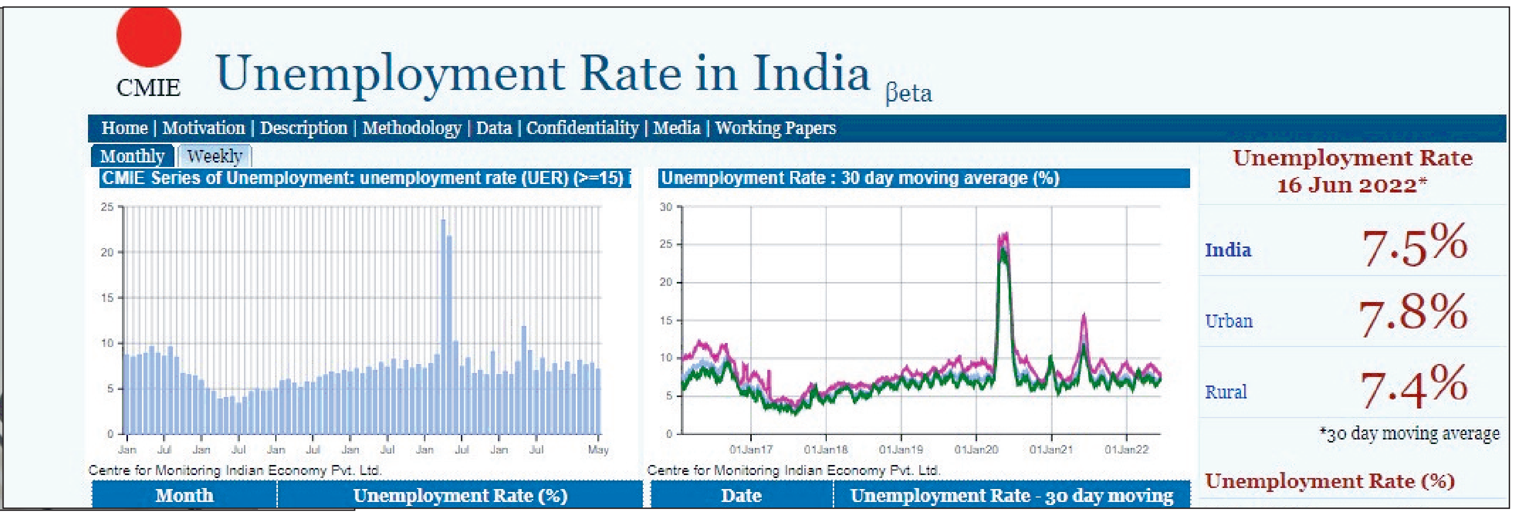

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देश में भले ही सेना भर्ती के नए प्रबंधन पर हंगामा मचा हो , भले ही युवा केंद्र के अग्निवीर योजना से असंतुष्ट हों , लेकिन उत्तराखंड की युवा धामी सरकार को बड़ी राहत मिली है। देश में रोज़गार कम होने की खबर तो आप खूब पढ़ते होंगे लेकिन न्यूज़ वायरस आपको एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बता रहा है जिसके मुताबिक़ उत्तराखंड ने रोज़गार के मामले में बेहतरीन कामयाबी हासिल कर ली है।

रोजगार के मामले में उत्तराखंड ने सभी हिमालयी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है. यानी उत्तराखंड अब उन राज्यों में शुमार हो गया है, जहां सबसे ज्यादा लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से जारी आंकड़ों ने उत्तराखंड की इस बेहतर स्थिति को जारी किया है.

राष्ट्रीय बेरोजगारी दर में उत्तराखंड पांचवें स्थान पर आ गया है.... उत्तराखंड की स्थिति मई महीने में बेरोजगारी दर को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी सबसे बेहतर दिखाई देती है. बेरोजगारी दर के लिहाज से उत्तराखंड सबसे अच्छे हालातों वाले राज्यों में पांचवें नंबर पर जगह बना चुका है. छत्तीसगढ़ में 0.7% बेरोजगारी दर है. वहीं, मध्य प्रदेश में 1.6% बेरोजगारी दर, तीसरे नंबर पर गुजरात 2.1% बेरोजगारी दर पर है तो उड़ीसा 2.6 प्रतिशत बेरोजगारी दर है. इसके बाद पांचवें नंबर पर उत्तराखंड है, जहां बेरोजगारी दर 2.9 आंकी गई है.

इन आंकड़ों से साफ है कि उत्तराखंड के साथ-साथ पूरे देश में बेरोजगारी को लेकर कोरोना का साल 2020 सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है. लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं और उत्तराखंड अब उन राज्यों में शुमार हो गया है, जो बेरोजगारी दर को दूर करने को लेकर सबसे बेहतर स्थिति में दिखाई देता है. मई महीने में सीएमआईई के आंकड़ों से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी इसे उत्तराखंड और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर बताती है....

लौटा नहीं बल्कि 47.3% बढ़कर 3.83 अरब स्विस फ्रैंक हुआ देश का काला धन

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

एक दौर था जब देश को काला धन लाउने की उम्मीद थी। राजनीति का पूरा खेल भी इसी एक शब्द के इर्द गिर्द नई कहानी लिख रहा था लेकिन आज 2022 की जून का महीना है और काला धन को लेकर अब जो खबर आई है वो भी जान लीजिये। भारतीय व्यक्तियों और फर्मों द्वारा स्विस बैंकों में जमा किया गया धन 2021 के अंत में 47.3% बढ़कर 3.83 अरब स्विस फ्रैंक (30,500 करोड़ रुपए से अधिक) पर पहुंच गया है। यह 14 साल में सबसे अधिक है। 2020 के अंत में भारतीय ग्राहकों के कुल 2.55 बिलियन स्विस फ्रैंक (20,700 करोड़ रुपए) जमा थे। इसके बाद लगातार दूसरे वर्ष इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। यह जानकारी स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक द्वारा गुरुवार को जारी सालाना आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है।

2006 में रिकॉर्ड स्तर पर थी बैंकों में जमा राशि

वर्ष 2006 में भारतीय व्यक्तियों और फर्मों की स्विस बैंकों में कुल जमा राशि लगभग 6.5 अरब स्विस फ्रैंक के रिकॉर्ड स्तर पर थी। इसके बाद कुछ वर्षों (2011, 2013, 2017, 2020 और 2021) को छोड़कर इसमें ज्यादातर घटने का रुझान रहा है। जबकि 2019 के दौरान सभी चार घटकों में गिरावट आई थी।

2020 में 212% बढ़ा भारतीयों का धन

स्विस बैंक की तरफ से 18 जून 2021 को जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया था कि भारतीयों के स्विस खातों में जमा पैसे 20,700 करोड़ तक पहुंच गए हैं, जो पिछले 13 साल में सबसे ज्यादा हैं। वहीं, 2019 की तुलना में यह 212% या 3.12 गुना ज्यादा हैं।

इस आंकड़े में भारत स्थित बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों के जरिए जमा की गई राशि भी शामिल थी। स्विस बैंकों में जमा बढ़ने की वजह सिक्योरिटीज और ऐसे ही दूसरे विकल्पों के जरिए होल्डिंग्स में तेज उछाल होना था। हालांकि, कस्टमर डिपॉजिट में लगातार दूसरे साल गिरावट आई थी।

कालाधन नहीं है सारा पैसा

ये आंकड़े स्विट्जरलैंड में भारतीयों द्वारा रखे गए काले धन को नही बताते हैं। इस डेटा में वह पैसा भी शामिल नहीं है जो भारतीयों, NRI या दूसरे लोगों के पास स्विस बैंकों में तीसरे देश की संस्थाओं के नाम पर हो सकता है। यह पैसा स्विस बैंकों की भारतीय ग्राहकों की 'कुल देनदारियों' से जुड़ा है, जिसमें व्यक्तियों, बैंकों और उद्यमों से जमा राशि शामिल है।

सुरक्षित हेमकुण्ड साहिब यात्रा की व्यवस्था जांचने गोविन्दघाट पहुंची एसपी श्वेता चौबे

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे लगातार चार धाम यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए अपनी टीम का कुशल नेतृत्व कर रही हैं। इसी का नतीजा है कि श्री बद्रीनाथ धाम एवं श्री हेमकुण्ड साहिब यात्रा निर्बाध रुप से चल रही है, आगामी बरसात के मौसम में कुशल एवं सुरक्षित हेमकुण्ड साहिब यात्रा व्यवस्था को और प्रभावी बनने के लिए पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे ने गोविन्दघाट, पाण्डुकेश्वर क्षेत्र का निरीक्षण किया । इस दौरान उन्होंने हेमकुण्ड साहिब यात्रा ड्यूटी में नियुक्त पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनी गई एवं उनके शीघ्र निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देश दिया । इसके साथ ही यात्रा के दौरान अच्छी ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों का उत्साहवर्धन करते हुए आगे भी मेहनत एवं लगन से ड्यूटी करने हेतु प्रेरित किया ।

निरीक्षण के दौरान एसपी श्वेता चौबे ने हेमकुण्ड साहिब यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं । आइए आपको बताते हैं चमोली पुलिस के ताज़ा यात्रा निर्देश क्या हैं -

- बरसात का मौसम प्रारम्भ होने से पूर्व थाने में आपदा सम्बन्धी उपकरणों की जाँच कर आवश्यक उपकरणों हेतु समय से माँग पत्र प्रेषित किया जाए।
- सभी पुलिस कर्मियों को रेनकोट उपलब्ध कराए जाएं।
- श्री हेमकुण्ड साहिब में इस वर्ष काफी संख्या में श्रद्घालुओं का आगमन हो रहा है जिसके चलते वाहनों की अधिकता के कारण वाहनों की पार्किंग के लिए अतिरिक्त पार्किंग हेतु खाली पड़ी जमीन का चयन कर सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया।
- दोपहिया वाहनों हेतु अलग से पार्किंग स्थल का चयन किया जाए।
- पार्किंग में खड़े यात्रियों के वाहनों की सुरक्षा हेतु थानाध्यक्ष गोविन्दघाट को रात्रि गस्त लगवाने हेतु निर्देश दिये गए।
- लामबगड़ में संकरे मार्ग के चौड़ीकरण हेतु सम्बन्धित विभाग से पत्राचार कर लिया जाए।
- पुलना से गोविन्दघाट तक शटल वाहनों को किराया निर्धारित करने एवं वाहनों पर अनिवार्य रुप से रेट लिस्ट लगवाने व यात्रियों से निर्धारित किराए से अधिक ना वसूलने दिया जाए।
- घोड़ा-खच्चर स्वामियों द्वारा यात्रियों से निर्धारित किराए से अधिक ना वसूला जाए एवं अनिवार्य रुप से रेट लिस्ट लगवाई जाए।
- सुरक्षा के दृष्टिगत गोविन्दघाट से दिन में 02:00 बजे बाद यात्रियों को हेमकुण्ड की तरफ ना भेजा जाए,एवं हेमकुण्ड साहिब से दिन में 3:00 बजे तक सभी यात्रियों को वापस भेजा जाए।
- थानाध्यक्ष गोविन्दघाट को बाहर से आए दुकानदारों, फड़-फेरी वालों, घोड़ा-खच्चर स्वामियों एवं होटल कर्मियों, नेपालियों एवं बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन अनिवार्य रुप से कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
- पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी पुलिस कर्मियों को सतर्कता से ड्यूटी करने, यात्रियों के साथ मैत्री व सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने, ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतने हेतु निर्देशित किया गया है।

अग्निपथ योजना, युवाओं को भड़का रहा विपक्ष : अजय भट्ट

फिरोज़ आलम 'गांधी' की विशेष रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

केंद्र सरकार ने एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना 'अग्निपथ' लॉन्च की, लेकिन देशभर के साथ ही उत्तराखंड में भी इसका जोरदार विरोध हो रहा है. युवा सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच सेना के ढांचे में बदलाव के मामले पर केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने इसे युवाओं के हित में बताया है. साथ ही कहा कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, और चीन की तर्ज पर अब भारत में भी सेना में बदलाव किया जा रहा है. जिससे आने वाले समय में एक मजबूत सेना उभर कर खड़ी होगी. इन सभी देशों के सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर किए अभ्यास के बाद लिए गए सर्वोत्तम फैसलों को भारत में प्रयोग किया जा रहा है.

सांसद अजय भट्ट उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा है. जिस वजह से आज देश में आंदोलन की स्थिति बनी है. युवा भ्रमित होकर सार्वजनिक व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं. विपक्ष की घबराहट के चलते इस तरह का प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया है. विपक्ष की ओर से सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है.

सरकार गुरिल्लाओं के लिए बना रही विशेष योजना

नैनीताल पहुंचे सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने कहा कि अग्निपथ योजना में सैनिकों के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होगा. पूर्व की भांति सभी सैनिकों को पेंशन व अन्य सुविधा सरकार की ओर से दी जाएगी. सरकार के इस फैसले से देश में तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी पर लगाम लगेगी और पहले से अधिक कुशल सेना का गठन होगा. अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र सरकार गुरिल्लाओं के लिए भी विशेष योजना बना रही है. जिससे गुरिल्ला युद्ध में सम्मिलित लोगों को भी फायदा मिलेगा.

विधानसभा सीढ़ी पर खानपुर विधायक उमेश कुमार का धरना

मो अरशद की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सदन में उनका सवाल ना लिए जाने पर सदन से बहिर्गमन किया. दरअसल उमेश कुमार क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड यानी CAU पर घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी ED और CBI से जांच करने की मांग कर रहे थे. वहीं बाहर आकर उन्होंने मीडिया से कहा कि अब वह इस विषय को कोर्ट में लेकर जाएंगे.

उत्तराखंड की खानपुर विधानसभा सीट से चुनकर आए निर्दलीय विधायक उमेश जे कुमार ने विधानसभा सत्र के दौरान क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में चली आ रही अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाना चाहा. लेकिन उनका सवाल नहीं लिया गया. जिसके बाद वो सदन का बहिष्कार करते हुए सदन से बाहर चले गए. बाहर आकर उन्होंने कुछ देर CAU के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया.

अग्निपथ योजना के नाम पर युवाओं से मजाक : जोत सिंह बिष्ट प्रदेश संगठन समन्वय, आप

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हमारे देश की शान है देश के युवा अपने देश की सेना में सेवा करते हुए अपने को पूर्ण रूप से देश सेवा के लिए समर्पित करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन भारतीय सेना में बीते 2 सालों से भर्ती प्रक्रिया पर रोक के कारण बताया जा रहा है कि लगभग 2 लाख पद रिक्त हैं।

सेना में भर्ती की पूर्व निर्धारित प्रक्रिया से इन पदों को भरने के बजाय भारत सरकार की कैबिनेट ने दो लाख रिक्त पदों में से मात्र 46 हज़ार पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के साथ अब 4 साल की संविदा पर भर्ती करने का प्रस्ताव पारित किया है।बिष्ट ने आगे कहा कि भारत सरकार का यह फैसला सेना के मनोबल को कमजोर करने के साथ-साथ सेना में भर्ती होने के लिए पिछले 2 सालों से दिन-रात तैयारी कर रहे नौजवानों के सपने पर कुठाराघात करने वाला है।आम आदमी पार्टी का मानना है कि भारत सरकार को अपने इस फैसले को बदल कर सेना के दो लाख रिक्त पदों पर पूर्व की प्रक्रिया के अनुरूप भर्ती शुरू करते हुए देश के वीर नौजवानों को पूरे समय तक सेवा का अवसर प्रदान करने का निर्णय लागू करना चाहिए। भारत सरकार द्वारा सेना में भर्ती के अपने इस फैसले को अग्निपथ का नाम देते हुए मात्र 4 साल के लिए ठेके प्रथा की तरह सेना में भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर नाम देकर महिमामंडन किया जा रहा है और भारत सरकार नासमझी भरे अपने इस फैसले पर अपनी पीठ थपथपा रही है लेकिन भारत सरकार का यह फैसला अपने नाम के अनुरूप सेना में भर्ती के इच्छुक नौजवानों को जलते अंगारों पर चलने के लिए धकेलता हुआ दिखाई दे रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि देश में आजादी के 75 साल में ऐसा पहली बार दिखाई दे रहा है कि भारत सरकार ने 46 हज़ार पदों पर भर्ती निकाली और उसके खिलाफ देश के अनेकों शहरों में नौजवान सड़कों पर उतर आए हैं। हम सीमावर्ती राज्य हैं उत्तराखंड की सीमाएं चीन और नेपाल से मिली हुई हैं। हमारे नौजवानों में राष्ट्रभक्ति का जज्बा कूट-कूट कर भरा है इसलिए उत्तराखंड के वीर जवान सेना में भर्ती को अपनी प्राथमिकता में रखते हैं लेकिन भारत सरकार के इस फैसले से राज्य का नौजवान हतप्रभ है।

कांग्रेस आंगनबाड़ी कार्यकर्तीयों के साथ ठग की राजनीति करना बंद करे : रेखा आर्या

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

सदन में उठे आंगनबाड़ी कार्यकर्तीयो के मानदेय के विषय पर मंत्री रेखा आर्या ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला । मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 2012 से 2017 तक राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही जिसमे इस दौरान केंद्र की और से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 4 हजार 500,आंगनबाड़ी सहायिका को 2 हजार 250 तो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 3 हजार 500 दिया जाता था ।वही इस दौरान राज्य में रही कांग्रेस सरकार की बात करे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 3 हजार , सहायिका को 1500 और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 1250 मानदेय मिलता था । उन्होंने साल 2012 से 2017 के बीच आंगनबाड़ी कार्यकर्तीयो के मानदेय बढ़ने के मामले पर जवाब देते हुए कहा कि इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मानदेय 1500 ,सहायिका का 750 और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का 1250 बढ़ाने का काम किया ,इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्तीयो के मानदेय में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नही हुई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जताया आभार कहा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में रहता है योगदान-रेखा आर्या

मंत्री रेखा आर्या ने आंगनबाड़ी केंद्रों में काम कर रही बहनों के मानदेय के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का योगदान सदैव राज्य की कल्याणकारी योजनाओं में रहता है जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद वक्त करती हूँ। मंत्री आर्या ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में जबसे भाजपा की सरकार आयी तब से लगातार अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि 2 नवम्बर 2021 को भाजपा सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में काम कर रही बहनों के बारे में सोचा और उनके मानदेय में वृद्धि की । जिसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 1800, सहायिका को 1500 और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 1500 रुपये की मानदेय दिया जाता है।

मंत्री रेखा आर्या ने मानदेय व्रद्धि के ऊपर जानकारी देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय में 9 हजार 300 , सहायिका के मानदेय में 5 हजार 250 और मिनी आंगनबाड़ीकार्यकर्ती के मानदेय में 6 हजार 250 की व्रद्धि की गई जो कि ऐतिहासिक है । मंत्री रेखा आर्या ने विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्तीयो का मानदेय 7500 ,छत्तीसगढ़ जहां 6500 है तो वहीं उत्तराखंड में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 9300 है जो कि सबसे ज्यादा और ऐतिहासिक है ।मंत्री रेखा आर्या ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस आंगनबाड़ी कार्यकर्तीयों के साथ ठग की राजनीति करना बंद करे। उन्होंने कहा कि काँग्रेस ये बताए कि जहां जहां उनकी सरकार रही वहां आंगनबाड़ी कार्यकर्तीयो के मानदेय में कितना इजाफा हुआ । उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों के लिए क्या कुछ किया। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्तीयो को सबसे ज्यादा मानदेय दिया जा रहा है ।हमारी सरकार सदैव आंगनबाडी कार्यकर्तीयो के हितों को लेकर लगातार कार्य कर रही है ।

प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है सुचारू रूप से -रेखा आर्या

उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को लेकर कहा कि राज्य में शुरुआती दौर में जब कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ा तो उसे देखते हुए प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया था ताकि कोई भी महिला संक्रमित ना हो लेकिन जब लोग वेक्सीनेटेड हो गए तो सरकार के निर्देशों के अनुसार 1 मार्च 2022 से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन शुरू कर दिया गया जो कि निर्वाद्ध रूप से चल रहे हैं। मंत्री रेखा आर्या ने टेक होम राशन के वितरण ना हो पाने के विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि टेक होम राशन प्रदेश के सभी जनपदों में दिया जा रहा है ,अगर किसी जिले में यह राशन का वितरण नही हो पा रहा है तो ऐसा नही है कि उस जनपद में टेक होम राशन का वितरण नही होगा ।मन्त्री आर्या ने बताया कि राज्य में टेक होम राशन हर माह की 5 तारीख को दिया जाता है कभी -कभी टेक होम राशन के वितरण में देरी हो सकती है लेकिन यह राशन सभी जनपदों में दिया जा रहा है । मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों का किराया ना दिए जाने के विषय पर सदन को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 7426आंगनबाड़ी केंद्र है जिनके किराये के लिए वर्ष 2021-22 में 10 करोड़ 55 लाख 32 हजार की धनराशि साशन द्वारा किराया मद में दो चरणों मे जारी की गई थी जिसमे से अगस्त माह 2021 में कोषागार के जरिये 7 करोड़ 9 लाख 25 हजार की धनराशि बाल विकास परियोजना अधिकारियों को आबंटित कर दी गई थी इसके सापेक्ष कोषागार द्वारा एसएनए के माध्यम से 5 करोड़ 88 लाख 65 हजार की धनराशि व्यय की गई थी तथा शेष धनराशि 59 लाख 18 हजार 550 बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा समय पर निदेशालय को समर्पित नही करने के कारण 31 मार्च 2022 को करनी पड़ी साथ ही अभी टेक्निकल समस्या की वजह से कुछ भबनो का किराया नही दे सके लेकिन इस वित्तीय वर्ष में बचे हुए भवनों का किराया दे दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'नभ नेत्र' का किया उद्घाटन, आपदा में होगा मददगार

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'नभ नेत्र' का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है, किसी भी आपदा की स्थिति में ड्रोन तकनीक पर आधारित यह मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन आपदा संबंधी डाटा जुटाने में कारगर साबित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नभनेत्र की सराहना की और साथ ही DARC की टीम को प्रमाणपत्र भी दिए।

आई.टी.डी.ए निदेशक अमित सिन्हा ने जानकारी दी कि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा आने या आपात स्थिति बनने के समय डेटा जुटाने, प्रोसेस करने और स्थिति पर निगरानी रखने जैसी चुनौतियां रहती हैं। अब इन तमाम मोर्चों के लिए ड्रोन तकनीक की मदद बड़े पैमाने पर ली जा सकेगी। इसके लिए ड्रोन एप्लिकेशन रिसर्च सेंटर ने मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन विकसित किया है जिसका उद्देश्य आपदा या आपातकालीन स्थिति के दौरान ड्रोन का उपयोग करने एवं ड्रोन के माध्यम से डेटा एकत्रित करने में किया जायेगा। इसके साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से आपदा पूर्व एवं आपदा पश्चात मानचित्र तैयार किया जाएगा। यह स्टेशन पूरी तरह एक वाहन पर स्थापित किया गया है। इस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को डेटा प्रोसेसिंग के लिए हाई स्पीड वर्कस्टेशन, बैंडविड्थ एग्रीगेशन और बिना नेटवर्क जोन वाले क्षेत्रों के लिए वी-सैट से युक्त किया गया है। इस वाहन का उपयोग उत्तराखंड सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन और सभी संवेदनशील आपदा संभावित क्षेत्रों की 3डी मैपिंग के लिए किया जाएगा।

इस अवसर पर आईटीडीए से नवनीत शौनक, शयान अली, हिमांशी राणा, याशिका पाण्डे, शिखा पाण्डे, शशांक मुटनेजा, विपिन कुमार, दीपांकर बिष्ट आदि उपस्थित थे।

धामी सरकार का बड़ा कदम, लैंड यूज चेंज की राह होगी आसान

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड विधान सभा सत्र से बड़ी खबर आयी है , आपको बता दें कि धारा 154 के तहत गैर कृषि प्रयोजन के लिए खरीदी गई भूमि, किसी भी विकास प्राधिकरण की ओर से गैर कृषि कार्यों के लिए स्वीकृत नक्शा और सिंगल विंडो सिस्टम से स्वीकृत निवेश प्रस्तावों के आधार पर एसडीएम को सात दिन के भीतर कृषि भूमि को किसी अन्य उपयोग में लाने की घोषणा का अधिकार दिया गया। घोषणा के तीन दिन के भीतर भू-उपयोग को खतौनी में दर्ज किया जाएगा।

उत्तराखंड में निवेशकों के लिए भू-उपयोग परिवर्तन (लैंड यूज चेंज) की राह आसानी होगी। सरकार ने निवेशकों की दिक्कतों को देखते हुए उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम) संशोधन विधेयक सदन में पेश किया है। इसके अलावा उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा अग्नि निवारक और अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक भी पटल पर रखे हैं।

उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम) संशोधन विधेयक में सरकार निवेशकों के लिए लैंड यूज चेंज को आसानी करनी जा रही है। धारा 154 के तहत गैर कृषि प्रयोजन के लिए खरीदी गई भूमि, किसी भी विकास प्राधिकरण की ओर से गैर कृषि कार्यों के लिए स्वीकृत नक्शा और सिंगल विंडो सिस्टम से स्वीकृत निवेश प्रस्तावों के आधार पर एसडीएम को सात दिन के भीतर कृषि भूमि को किसी अन्य उपयोग में लाने की घोषणा का अधिकार दिया गया। घोषणा के तीन दिन के भीतर भू-उपयोग को खतौनी में दर्ज किया जाएगा।

बजट सत्र की कार्यवाही 22 घंटे 43 मिनट तक चलाने पर सबका शुक्रिया : ऋतु खंडूरी, स्पीकर

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड की पांचवी विधानसभा का चार दिवसीय बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विपक्ष एवं पक्ष के सभी सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेशहित एवं जनहित के अनेक विषयों पर सदन में दोनों दलों द्वारा शांति पूर्वक गंभीर चिंतन-मनन किया गया। चार दिवसीय बजट सत्र की कार्यवाही 22 घंटे 43 मिनट तक चली।सत्र के दौरान विधान सभा को 573 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें स्वीकार

14 अल्पसूचित प्रश्न में 4 उत्तरित,190 तारांकित प्रश्न में 61 उत्तरित,339 आतारांकित प्रश्न में 165 उत्तरित,कुल 17 प्रश्न अस्वीकार एवं 3 विचाराधीन रखे गए. 9 याचिकाओं में से सभी याचिका स्वीकृत की गई. नियम 300 में प्राप्त 76 सूचनाओं में से 21 सूचनाएं स्वीकृत, 26 सूचनाएं ध्यानाकर्षण के लिए, नियम-53 में 54 सूचनाओं में 6 स्वीकृत एवं 20 ध्यानाकर्षण के लिए रखी गई.नियम-58 में प्राप्त 32 सूचनाओं में 14 को स्वीकृत किया गया.नियम-310 में 4 सूचना प्राप्त हुई, जो कि नियम 58 में परिवर्तित की गई.

विधेयक : 1. उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 20222. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 20223. उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 20224. उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2022

प्रतिवेदन

1. आर्थिक सर्वेक्षण उत्तराखण्ड, वर्ष 2021- 22 खण्ड-12. उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तुत वार्षिक/विशेष रिपोर्ट, 2012-18 एवं 2018-193. महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या-1 वर्ष 20224.उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (अवधि 01 अप्रैल, 2020से 31 मार्च, 2021 तक)5. उत्तराखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 की धारा 16 (2) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट

राहुल गाँधी के समर्थन में सड़कों पर फिर हुआ देहरादून कांग्रेस का प्रदर्शन

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून महानगर कांग्रेस कमेटी ने केन्द्र सरकार के इशारे पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी का ईडी के माध्यम से उत्पीड़न कराये जाने तथा कांग्रेस मुख्यालय पर भाजपा के इशारे पर दिल्ली पुलिस द्वारा की गई दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में देहरादून में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया।

पूर्व विधायक राजकुमार और महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में महानगर के कांग्रेसजनों ने प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।

महानगर कांग्रेस ने भाजपा की केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र की वर्तमान सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध और द्वेष की भावना से काम किया जा रहा है। अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के लिए केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी दल के नेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है जिसकी कांग्रेस पार्टी कठोर शब्दों में निन्दा करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार के जन विरोधी फैसलों के खिलाफ जनता की आवाज बनकर उभरे हैं जो निकम्मी मोदी सरकार को रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र देश में स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज बनी थी । इसीलिए 1942 से 1945 तक अंग्रेजों द्वारा ''भारत छोड़ो आंदोलन'' के दौरान इस समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसे महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक त्रासदी के रूप में वर्णित किया था।

भेड़ बकरी पालको की आजीविका और जीवन स्तर में सुधार हमारा लक्ष्य : सौरभ बहुगुणा, पशुपालन मंत्री

राज्य भेड़ बकरी अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन व कृत्रिम गर्भाधान प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ

विशेष रिपोर्ट - आशीष तिवारी
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

केंद्रीय मंत्री डा0 संजीव कुमार बालियान,ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन, भारत सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड विकास बोर्ड (यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0) के तत्वाधान में उत्तराखण्ड राज्य के भेड़ बकरी पालको हितार्थ संचालित (Heat Synchronization and Artificial Insemination in Sheep and Goat) तथा (Heat Synchronization and Artificial Insemination through Imported Merino Sheep) योजनान्तर्गत निर्मित राज्य भेड़ बकरी अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन व कृत्रिम गर्भाधान प्रयोगशाला, पशुलोक, ऋषिकेश का लोकापर्ण व उद्घाटन किया।

केन्द्रीय राज्य मंत्री के साथ-साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा डा0 आर0 मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव मुख्यमंत्री तथा डा0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोतम सचिव, पशुपालन, ने कृत्रिम गर्भाधान प्रयोगशाला का उद्घाटन कार्यक्रम में आये राज्य के भेड़ बकरी पालको को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें ज़रूरी सामग्री वितरित की

आपको बता दें कि इस प्रयोगशाला में बीते दिसम्बर 2019 में आस्ट्रेलिया से आयातित उच्च गुणवत्ता के मैरीनो मेढ़ो के Germ Plasm तथा सिरोही, बरबरी, जमुनापारी, बीटल, जाखराना प्रजाति के बकरों के वीर्य का उत्पादन करते हुये राज्य में व्यापक स्तर पर संचारित किया जाएगा तथा राज्य के भेड़ व बकरी पालकों के द्वारा पर वीर्य की उपलब्धता कराते हुये पूरे राज्य में भेड़ बकरियों में नस्ल सुधार का कार्य किया जाएगा। जिससे भेड़ के ऊन गुणवत्ता में वृद्वि के साथ-साथ भेड़ व बकरियों के वजन में वृद्वि होगी तथा भेड़ बकरी पालको की आजीविका व जीवन स्तर पर सुधार होगा। उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के माध्यम से संचालित योजनान्तर्गत वर्तमान तक लगभग 3000 भेड़ व बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान किया गया है। साथ ही उच्च गुणवत्ता के नर Germ Plasm को स्थानीय भेड़ों में संचारित करने व नस्ल सुधार के लिए दूरबीन से कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी का उपयोग भी किया जाएगा।

उत्तराखण्ड राज्य के भेड़ बकरी कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी को प्रोत्साहित व लोकप्रिय करने के उद्देश्य से राज्य के बेरोजगार नवयुवक व नवयुवतियों को भेड़ बकरी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकताओं का प्रशिक्षण व कौशल विकास किया जा रहा है जिससे उन्हे आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होगें।इस कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय मंत्री ने कृत्रिम गर्भाधान कार्यकताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान करने हेतु प्रयोगशाला में निर्मित अतिहिमीकृत वीर्य के 50 डोज भी वितरित किये। इस दौरान राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, भारत सरकार के सहयोग से संचालित राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना-भेड़ बकरी सेक्टर योजना के अन्तर्गत बकरी के दूध एवं दूध से निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु BAKRAW Sweets ब्रांड का उद्घाटन किया गया।

राज्य के पशुपालन मंत्री और युवा विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन, भारत सरकार के सहयोग से भेड़ बकरी पालकों के हितार्थ संचालित योजनाओं से राज्य की भेड़ व बकरियों में प्राकृतिक व कृत्रिम गर्भाधान से नस्ल सुधार का कार्य किया जा रहा है तथा भेड़ बकरियों में ऊन की गुणवत्ता तथा मांस उत्पादन वृद्वि से राज्य के भेड़ बकरी पालको की आजीविका व जीवन स्तर में सुधार होगा। कृत्रिम गर्भाधान पैरावेट्स में कौशल विकास स्थानीय बेरोजगार नवयुवको को स्वरोगार के साधन उपलब्ध होगें। उन्होंने कहा कि धामी सरकार का लक्ष्य है कि इन प्रयासो से भेड़ बकरी पालको को कुशल उद्यमी बना कर उत्तराखंड को आने वाले दिनों में एक मिसाल के तौर पर देश के सामने खड़ा किया जाये।

संपादकीय

हमारे संचार माध्यमों की हिंदी

साहित्य, आलोचना और सृजनशील साहित्यकारों के संसार से मीडिया कुछ अलग तरह का क्षेत्र है. मीडिया को सृजनशील रचना की अपेक्षा दैनंदिन जीवन की घटनाओं को यथातथ्य प्रस्तुत करना होता है. इसलिए, उसे अपनी अलग भाषा चाहिए, एक सीमा तक अंग्रेजी के आम शब्द आना स्वाभाविक है, क्योंकि देश में अंग्रेजी का वर्चस्व है. मध्य और निम्न मध्यवर्ग ही नहीं, आर्थिक रूप से सबसे निचले पायदान वाले वर्ग को भी अपनी पहचान के लिए अंग्रेजी का तड़का चाहिए. शिक्षा, चिकित्सा, न्यायालय, विधायिका और प्रायः हर जगह अंग्रेजी का बोलबाला है. जिसका बोलबाला होता है, लोग उसकी नकल करते हैं. इसका आशय यह नहीं है कि जो सृजनशील साहित्य नहीं है, उसमें अंग्रेजी को खुली छूट मिले. प्रश्न भी उठता है कि नकल कितनी और कैसी हो. ऐसी भी क्या नकल कि कथित हिंदी वाक्य में केवल क्रियापद को छोड़ कर सारे शब्द अंग्रेजी के ठूंसे हुए हों. स्वभाविक रूप से प्रयुक्त अंग्रेजी और ठूंस-ठूंस कर डाली हुई अंग्रेजी में अंतर पहचानना चाहिए. मीडिया शायद यह भूल जाता है कि ऐसी हिंदी से लपेट कर परोसी जानेवाली सामग्री के प्रति पाठकों में भी अरुचि पैदा होती है. द्विवेदी युग में पत्रकारिता में सहज, बोलचाल की हिंदी का ही रास्ता था. उस हिंदी की बुनावट में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पश्तो आदि से भी ऐसे शब्दों को लिया गया, जो आम लोगों के दैनिक व्यवहार का हिस्सा थे. पिछली सदी के सातवें-आठवें दशक तक भी आमफहम भाषा से आशय यही था कि जो भाषा चाय के ढाबे में, मजदूरों की टोली में, बाजार में खरीद-बिक्री कर रहे लोगों की समझ में आये और साथ ही साथ पढ़े-लिखे मध्यमवर्ग को भी उससे जुड़ाव महसूस हो. सभी माध्यम (तब समाचार पत्र ही अधिक थे) कमोबेश यही नीति अपना रहे थे. एक ओर अज्ञेय, धर्मवीर भारती, विद्यानिवास मिश्र, रघुवीर सहाय जैसे चोटी के साहित्यकार भी पत्रकारिता कर रहे थे और दूसरी ओर राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, एसपी सिंह, ज्ञानरंजन जैसे भी थे, जो प्रथम दृष्टया हिंदी साहित्य के मूर्धन्य लेखकों में नहीं गिने जाते, किंतु पत्रकारिता में उनका अमूल्य योगदान है. परंपरागत मीडिया की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि भाषा की मर्यादा से किसी तरह का कोई समझौता न हो. उसके लिए पत्रकार एवं लेखक व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में गंभीर अध्ययन करते थे, ताकि भाषा के स्थापित मानकों के साथ कोई समझौता न हो. आज पाठकों का आयुवर्ग, सामाजिक दायरा, रुचियां, प्राथमिकताएं बदल गयी हैं. परिणामस्वरूप विषय, भाषा और शैली में भी बदलाव जरूरी हो गया. इस बदलाव का आशय यह नहीं हो सकता कि संवाददाता फील्ड से या प्रस्तोता स्टूडियो से जो दे रहे हैं, उसका संपादकीय कक्ष में पूर्व संपादन न हो, उन पर भाषा का कोई अंकुश न हो, परंतु दुर्भाग्य से जो मीडिया उत्पाद परोसा जा रहा है, उसमें भाषा के प्रति बड़ी ही लापरवाही का दृष्टिकोण है. यदि मीडिया की हिंदी को आम लोगों के करीब लाना है, तो वह ऐसी परिष्कृत हिंदी या किताबी हिंदी नहीं हो सकती, जो बोलचाल की हिंदी से अपने को दूर रखती आयी है. समय के साथ मीडिया की बढ़ी ताकत ने उसे एक जिम्मेदारी भी दी है कि वह नयी पीढ़ी को भाषा के संस्कार भी दे. इस जिम्मेदारी को समझे जाने की जरूरत है. प्रायः तर्क दिया जाता है कि समाचार पत्रों की भाषा विशुद्ध साहित्यिक नहीं होती. तर्क अपनी जगह ठीक है, किंतु वह गली-चौराहे की आमफहम भाषा भी तो नहीं हो सकती. इन दोनों सिरों के बीच में ही कहीं मीडिया की भाषा की स्थिति होनी चाहिए और प्रत्येक संस्थान को अपनी भाषा नीति तय करनी चाहिए. यदि आवश्यक हो तो समय-समय पर उसमें बदलाव भी हो. तेज गति से बदलते परिवेश, मान्यताएं, तकनीक और दूसरी ओर पाठक/ दर्शक वर्ग के जीवन स्तर, शिक्षा स्तर आदि को देखते हुए मीडिया में पिछली सदी की लगभग स्थिर-सी हो गयी हिंदी की अपेक्षा करना भी तर्कसंगत नहीं है. कोई भी जीवित भाषा बदलते परिवेश के साथ नयी शब्दावली, शैली और नयी अभिव्यक्तियों को ग्रहण करती है. फिर भी, सहजता और सरलता जैसे अनिवार्य गुणों से समझौता करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

सावधान ! अलर्ट है उत्तराखंड पुलिस सोशल मीडिया पर न फैलाएं अफवाह

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देश और प्रदेशों में मौजूदा हालात पर देवभूमि उत्तराखंड की मित्र पुलिस अब पूरी तरह से चौकन्नी हो गयी है। प्रदेश में प्रदर्शनकारियों और अफवाह फैलाने वाले सावधान हो जाएं क्योंकि डीजीपी ने शरारती तत्वों और साइबर क्राइम में लिप्त अपराधियों पर नज़र टेढ़ी कर दी है।

उत्तराखंड पुलिस के मुखिया डीजीपी अशोक कुमार ने परिक्षेत्र एवं जनपद प्रभारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रतिक्रियाओं के बाद प्रदेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के सम्बन्ध में एक बड़ी बैठक की।

उत्तराखंड पुलिस के मुखिया डीजीपी अशोक कुमार ने परिक्षेत्र एवं जनपद प्रभारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रतिक्रियाओं के बाद प्रदेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के सम्बन्ध में एक बड़ी बैठक की। डीजीपी अशोक कुमार ने जनपद प्रभारियों को अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेन्टर संचालकों एवं प्रदर्शनकारी युवाओं से वार्ता करें और यह सुनिश्चित कर लें कि किसी भी स्थिति में शान्ति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित न हो। प्रदेश में किसी भी कीमत पर माहौल नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति असंवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करके शान्ति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित करता है, तो उसके विरूद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाये।

बैठक में जो निर्देश डीजीपी ने दिए व आप ज़रूर पढें -

1. अपने-अपने जिला मजिस्ट्रेटों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त करा लिये जाये तथा समय से आवश्यक पुलिस प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाये।

2. देश के अन्य राज्यों में होने वाली प्रतिक्रियाओं पर सतर्क दृष्टि रखते हुए राज्य में इसका प्रभाव न पड़ने दिया जाये ।

3. जनपद क्षेत्रान्तर्गत जिला मुख्यालयों, महत्वपूर्ण संस्थानों, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल मार्ग, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डो, बाजारों, भीड-भाड वाले स्थलों एवं महत्वपूर्ण स्थलों आदि पर आवश्यकतानुसार पुलिस/पीएसी बल को दंगा नियंत्रण उपकरणों, टियर गैस आदि के साथ नियुक्त किया जाये।

4. यातायात को सुचारु रुप से संचालित कराये जाने हेतु पूर्व से एक कार्ययोजना तैयार कर ली जाये तथा आवश्यकतानुसार उसका उपयोग किया जाये ।

5. जनपद प्रभारी स्वयं भी लगातार सतर्क दृष्टि रखते हुये छोटी से छोटी घटनाओं पर नियमानुसार कार्यवाही कराते हुए कार्यक्रमों की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी अवश्य कराएं।

6. जनपद में स्थापित सोशल मीडिया मॉनीटरिंग सैल, सोशल मीडिया प्रमोशन सैल एवं साईबर सैल के माध्यम से सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली खबरों पर भी सतर्क दृष्टि रखें और तत्काल उनका खण्डन कराते हुए सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना एवं सुरक्षा- ए पी अंशुमान, पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र - करन सिंह नगन्याल, पुलिस उप महानिरीक्षक, पी/एम- सेंथिल अबुदेई कृष्ण राज एस, पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था- पी0 रेणुका सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

केंद्रीय मंत्री संग युवा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गिनाए योग के फायदे

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

केंद्रीय राज्य मंत्री पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन भरत सरकार मंत्री संजीव बालियान परमार्थ निकेतन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्वाभ्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन के विकास की अपार संभवनाएं मौजूद हैं, इससे लोगों को स्वरोजगार के बहुत से साधन उपलब्ध हो सकते हैं तथा उनकी आर्थिकी भी मजबूत हो सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में अनेक योजनाएं संचालित की है, जिनका उचित व प्रभावी क्रियान्वयन होने पर उत्तराखंड की दिशा व दशा बदल सकती है। उन्होंने इन क्षेत्रों से सम्बंधित योजनाओं व कार्यक्रमों के संबंधों में केंद्र सरकार से उत्तराखंड को हर सम्भव आश्वाशन दिया। केंद्रीय मंत्री बलियान ने कहा कि उत्तराखंड आध्यात्मिकता व प्राकृतिक सुंदरता से अभिभूत है तथा वह गंगा घाट पर गंगा के मनोहारी और सुरम्य नजारे से मन्त्रमुग्ध हुए। उन्होंने सभी को आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया। इस दौरान वन मंत्री उत्तराखंड सरकार सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत के योगा को विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए बड़ा योगदान किया है। उनके ही अथक प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस दौरान पशुपालन मंत्री उत्तराखंड सौरभ बहुगुणा ने अपने संबोधन में कहा कि योग करने से जीवन शैली और अनेक मानसिक रोगों से छुटकारा मिलता है तथा एक लंबा व स्वस्थ जीवन जीने का अवसर भी प्राप्त होता है। स्थानीय विधायक रेनू बिष्ट ने कहा कि योग के महत्व को देखते हुए इसे पहाड़ी क्षेत्रों में भी अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए, जिससे वहां के लोग भी स्वस्थ व संतुलित जीवन जीने का आनंद ले सकें। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 काउंटडाउन का स्वागत संबोधन सचिव पशुपालन डॉ. बीवी आरसी पुरुषोत्तम द्वारा किया गया तथा इस दौरान जिलाधिकारी पौड़ी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे, निदेशक पशुपालन डॉ. प्रेम कुमार, साधवी परमार्थ निकेतन भगवती सरस्वती, अपर निदेशक पशुपालन डॉ. अविनाश आनन्द, ब्लॉक प्रमुख आशा भट्ट, परियोजना समन्वयक भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड डॉ. कमल सिंह सहित योगा में प्रतिभाग करने वाले लोग उपस्थित थे।

FIR नंबर - 155, जुर्म - बलात्कार घटना स्थल - 5 स्टार होटल, देहरादून

आरोपी,15 साल का मंदबुद्धि नाबालिग और शिकायतकर्ता,शादीशुदा होटलकर्मी महिला

मो सलीम सैफी
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून। 5 स्टार होटल में अगर बलात्कार की घटना हो जाए,आरोपी हो महज़ 15 साल का मंदबुद्धि नाबालिग लड़का और शिकायतकर्ता हो एक शादीशुदा महिला जो उसी होटल की कर्मचारी हो तो घटना को हम सनसनीखेज कह सकते है, ऐसे में अगर होटल प्रबंधन प्रेस के प्रवेश पर रोक लगा दे तो मामला संदिग्ध की परिधि में भी आ ही जायेगा,चलिए अब बात करते है विस्तार से।

राजधानी देहरादून के एक 5 सितारा होटल की एक शादीशुदा महिलाकर्मी जो पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी की रहने वाली है, उसने संबंधित पुलिस थाने में एक तहरीर देकर आरोप लगाया है कि होटल में ठहरे 15 साल के एक नाबालिग लड़के ने उस महिला का उस वक्त बलात्कार कर दिया जब वो महिला लेडीज़ वाशरूम में अकेली थी और मोबाइल चार्जिंग पर लगा रही थी,मौका पाकर लड़का वाशरूम में घुसा,महिला से हाय हैलो करा,महिला ने एतराज़ किया तो आरोपी नाबालिग ने दरवाज़े को अंदर से बंद करके बलात्कार को अंजाम दिया,महिला रोई चिल्लाई,मदद मांगी मगर आवाज़ बाहर नहीं गई इसलिए कोई उसकी मदद नहीं कर पाया,लड़का अपराध पूर्ण करने के बाद भाग गया और महिला ने होटल प्रबंधन को अपराध से रूबरू कराया ,उसके बाद होटल प्रबंधन की जांच पड़ताल से मालूम चला कि आरोपी छत्तीसगढ़ के एक रईस खानदान से है और वो अपने परिवार के साथ लगभग 22 हज़ार रुपए प्रतिदिन किराए के कमरे में ठहरा हुआ है,सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर घटी इस घटना की सूचना शाम को 5 बजकर 41 मिनट पर संबंधित थाने को दी गई जो घटनास्थल से मात्र 5 किलोमीटर दूर है यानी लगभग 8 घंटे बाद पुलिस को पता चला कि छत्तीसगढ़ के एक रईस नाबालिग ने बंगाल निवासी एक 5 स्टार होटल कर्मी को अपनी कामुकता का शिकार बना लिया है,धारा 376 के तहत मामला दर्ज करके पुलिस हरक़त में आई, हरक़त में इतनी आई कि पहले से होटल प्रबंधन के पास बंधक नाबालिग आरोपी को पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया,फिर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए देर रात मेडिकल टेस्ट को औचरिकताएं भी निभा ली है।

इस मामले में एसएसपी देहरादून जन्मेजय खंडूरी ने बताया कि आरोप संगीन है और परिस्थितियां विरोधभासी लिहाज़ा पुलिस जांच पूर्ण होने पर ही सच्चाई सामने आयेगी,उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि आरोपी साक्ष्य के आधार पर 15 साल का नाबालिग है लेकिन शारीरिक दृष्टि से ऐसा प्रतीत नही हो रहा,इतना ज़रूर है कि आरोपी मानसिक तौर पर मंदबुद्धि भी प्रतीत हो रहा है ऐसे में जांच अधिकारी की रिपोर्ट आने तक बुनियादी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है लेकिन इतना ज़रूर है कि किसी भी बेगुनाह के साथ अन्याय नहीं होगा,जांच एकदम निष्पक्ष और कानून की मर्यादा के अनुरूप ही होगी दूसरी ओर होटल प्रबंधन के महाप्रबंधक ने इतना कहा कि जैसे ही उन्हें घटना का पता चला तो उन्होंने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले दिया और एफआईआर दर्ज करा दी,पुलिस जांच कर रही है। आरोपी के परिजनों से हमने सम्पर्क साधने का प्रयास किया लेकिन उनसे संपर्क नही हो पाया, न तो पुलिस ने और न ही होटल प्रबंधन ने उनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध कराई। निष्पक्ष पत्रकारिता के आधार पर कुछ सवाल इस घटना को संदिग्ध होने की तरफ इशारा कर रहे है।

कुछ जांच योग्य सुलगते सवाल. ?

1.क्या 15 साल का एक रईस मंदबुद्धि नाबालिग लड़का एक 5 स्टार होटल के महिला वाशरूम में जाकर बलात्कार कर सकता है।

2.क्या शिकायतकर्ता होटलकर्मी शादीशुदा महिला को पूरे 5 स्टार होटल में मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉवर सॉकेट कही नही मिला,जो मोबाइल चार्जिंग के लिए वाशरूम में रही।

3.जिस 5 स्टार होटल के एक कमरे का प्रतिदिन किराया 22 हज़ार से ज्यादा हो तो वहा ठहरने वाला करोड़पति से कम तो नहीं हो सकता और वो अपने माता पिता के साथ होते हुए क्या ऐसा अपराध अंजाम दे सकता है।

4.क्या ये संभव है कि भारी सुरक्षा व्यवस्था और सैकड़ों कर्मचारियों की आवाजाही के बीच महिला वाशरूम में ऐसी घटना हो जाए और कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी न सुन पाए यानी 5 स्टार होटल किसी भी महिला गेस्ट के लिए सुरक्षित नही ।

5.घटना सुबह 9 बजकर 30 मिनट और 5 किलोमीटर दूर संबंधित थाने को 5 बजकर 41 मिनट पर सूचना यानी विलंब सूचना का क्या कारण रहा।

6.कही किसी हाई प्रोफाइल शख्स को बचाने की स्क्रिप्ट तो नही लिखी गई या फिर सॉफ्ट टारगेट का तंत्रमंत्र

7.फाइव स्टार होटल के कमज़ोर और लाचार सुरक्षा तंत्र के फेल होने से गेस्ट कितने सुरक्षित है।

8.होटल में प्रेस के प्रवेश पर रोक,आरोपी और शिकायतकर्ता से मिलने पर होटल प्रबंधन द्वारा प्रतिबंध क्यों,होटल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवालिया निशान की आहट

अब लाइलाज नहीं रहेगा एड्स, सिर्फ एक इंजेक्शन से मरीज होंगे ठीक

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

जून 2022 का महीना मेडिकल जगत के इतिहास में बेहतरीन कामयाबियों भरा महीना माना जा रहा है। इस महीने में अब तक अमाशय और सर्वाइकल कैंसर के दो भरोसेमंद उपचार आ चुके हैं और अब एड्स का टीका विकसित किए जाने की खबर है। आइए न्यूज़ वायरस की रिसर्च टीम आपको बता रही है क्या है पूरा मामला...

दुनिया में लाइलाज माने जाने वाली बीमारी एड्स के उपचार को लेकर इजरायल के वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली है। वैज्ञानिकों का दावा है कि जीन एडिटिंग से एक वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, जिससे एड्स का इलाज संभव होगा। रिसर्च को इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी की द जॉर्ज एस वाइस फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज के शोधार्थियों ने किया है।

एचआइवी वायरस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर हमला करता है। इसके बाद शरीर की प्रतिरोधक क्षमता वायरस से लड़ने में सक्षम नहीं होती ।टाइप बी व्हाइट ब्लड सेल्स से बना वैक्सीनइस रिसर्च को लेकर प्रकाशित शोधपत्र में वैज्ञानिकों ने दावा किया कि जीन एडिटिंग की मदद से टाइप बी व्हाइट ब्लड सेल्स का इस्तेमाल कर वैक्सीन तैयार की गई है। यह वैक्सीन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय करती है। इससे शरीर में एंटीबॉडी तैयार हो जाती है।

यह वैक्सीन एड्स को खत्म करने में सक्षम है ।वायरस ने स्वरूप बदला तो बी कोशिकाएं भी बदल जाएंगीवैज्ञानिकों द्वारा तैयार बी कोशिकाएं वायरस के संपर्क में आकर वायरस को अलग-अलग तोड़कर इनके खिलाफ लड़ती हैं। यदि वायरस बदल जाता है तो बी कोशिकाएं भी उसी अनुरूप स्वरूप को बदल लेती हैं। शोध से जुड़े डा. बारजेल का कहना है, बी सेल जीनोम तैयार करने में सफल रही है। सभी लैब मॉडल को टेस्ट किया गया है और शरीर में इलाज के दौरान जरूरी बी सेल्स को तैयार करने में सफलता मिली है। हमने खून में एंटीबॉडी तैयार किया, जो एचआइवी को खत्म करने में सक्षम है।

एक सीट से तीन बीवियां लड़ रही चुनाव बेचारा पति किसका करे प्रचार ?

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

खबर ऐसी है कि आप भी यकीन नहीं करेंगे लेकिन है ये एकदम सच ... यूँ तो तीन बीवियां रखना ही बड़े कलेजे की बात है उस पर उन्हें चुनाव मैदान में उतार कर बेचारे पति की तो जैसे सहमत ही आ गयी है। चलिए आपको एमपी ले चलते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश अजब है और गजब भी , सिंगरौली जिले में एक पंचायत सचिव की तीन पत्नियां हैं। तीनों पंचायत चुनाव लड़ रही हैं। दो तो एक ही पंचायत से सरपंच चुनावों में आमने-सामने हैं। तीसरी जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही है। पंचायत सचिव पर प्रचार के लिए पत्नियों का दबाव है। इस वजह से उसने अब घर ही नहीं बल्कि गांव भी छोड़ दिया है।

सिंगरौली जिले के जनपद पंचायत देवसर अंतर्गत घोंघरा पंचायत के सचिव सुखराम सिंह की तीन पत्नियां हैं। सुखराम की पहली पत्नी देवसर जनपद सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी पत्नी कुसुमकली व तीसरी गीता सिंह ने पिपरखड़ ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए नामांकन दाखिल किया है । अब कुसुमकली तो पहले भी सरपंच रही है, गीता सिंह की उम्मीदवारी से सुखराम का सुख-चैन उड़ गया है। दोनों ही चाहती हैं कि सुखराम उनके लिए प्रचार करें। अब परेशानी इतनी बढ़ गई है कि सुखराम ने गांव और घर से कुछ दिन के लिए रुखसत ले ली है।

पत्नियों को परेशानी नहीं तो कार्रवाई कैसे होगी ?

जनपद सीईओ बीके सिंह ने हिन्दू अधिनियम के विरुद्ध जाकर तीनों को दस्तावेज में पत्नी बताने पर नोटिस थमा दिया। हालांकि, अभी तक नामांकन खारिज नही हुआ है। देवसर एसडीएम आकाश सिंह का कहना है कि किसी भी पत्नी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। जब पत्नियों को कोई समस्या नहीं है तो कार्रवाई का सवाल भी फिलहाल नहीं उठता। जब कोई शिकायत आएगी, तब जरूर कार्रवाई की जाएगी।

दैनिक
न्यूज वायरस

न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, मेरठ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मौ. सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से मुद्रित एवं 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखंड) से प्रकाशित।

सम्पादक :
मौ. सलीम सैफी
कार्यकारी सम्पादक
आशीष तिवारी
दूरभाष : 0135-2672002

email-dainiknewsvirus@gmail.com
RNI No.- UTTHIN/2012/44094

वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय मान्य होगा